RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 352
दि. 25.04.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'लैब टू लैंड' का सपना हुआ सच, योगी बोले- तकनीक और नवाचार से बदली प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश में 'लैब टू लैंड' की अवधारणा सफल हुई है।

लखनऊ। (जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखनऊ में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र) के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह बदलाव वैज्ञानिक तकनीकों, एग्रो-क्लाइमेटिक जोन आधारित रणनीति तथा केंद्र-राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। यूपी में ह्लैब टू लैंडह्व की अवधारणा धरातल पर उतर चुकी है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है।

कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में रिकॉर्ड सुधार, बहुफसली खेती का विस्तार और वैल्यू एडिशन पर बढ़ता फोकस इस परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों, अंतरराष्ट्रीय कृषि केंद्रों की स्थापना, कृषि विज्ञान केंद्रों के सशक्तीकरण और प्रगतिशील किसानों की भूमिका को इस बदलाव का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

भिन्न-भिन्न एग्रो-क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप बनें नीतियां

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न एग्रो-क्लाइमेटिक जोन होने के कारण नीतियां भी उसी अनुरूप तय की जानी चाहिए। यदि अलग-अलग जोन में इस प्रकार की गोष्ठियां आयोजित की जाएं तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि गत वर्ष ह्यविकसित कृषि अभियान' और ह्यखेती की बात, खेत में' कार्यक्रम के दौरान उन्हें कई जनपदों में जाने का अवसर मिला, जहां किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि शिक्षा से जुड़े प्रशिक्षुओं में अभूतपूर्व उत्साह व जिज्ञासा देखने को मिली।

पहली बार इनोवेशन को सीधे व्यावहारिक धरातल पर उतारने का अवसर मिला है। पहले लैब में होने वाले अनुसंधान को लैंड तक पहुंचने में काफी समय लगता था, लेकिन अब ह्लैब टू लैंडह्व की अवधारणा साकार हो चुकी है और तकनीक सीधे खेत तक पहुंच रही है। इस अभिनव पहल के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से देशभर में लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

योजनाओं की सही जानकारी मिले तो किसान स्वयं बेहतर परिणाम देने में सक्षम

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, आवश्यकता केवल प्रभावी नेतृत्व की है, जिसकी शुरूआत भारत सरकार के स्तर से होती है और राज्य उसे तेजी से अपनाते हैं। पहले नीतियां केवल औपचारिक आयोजनों तक सीमित रह जाती थीं, लेकिन अब उनके ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। अन्नदाता किसानों को योजनाओं की सही जानकारी दी जाए, तो वे स्वयं बेहतर परिणाम देने में सक्षम हैं।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 की स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय प्रदेश में मात्र 69 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) थे, जो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे और उनके वैज्ञानिक भी अन्य संस्थानों में अटैच थे। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 20 नए केवीके की पहल के साथ-साथ मौजूदा केंद्रों को सशक्त बनाने की कार्ययोजना पर काम हुआ। आज स्थिति यह है कि सभी केवीके सक्रिय होकर नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रदेश के सभी 9 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से कृषि विकास को नई दिशा दे रहे हैं।

अब कृषि को वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर डेमोंस्ट्रेशन करते हैं और फिर किसानों के खेत में जाकर उसे लागू करते हैं, लगातार दौरे करते हैं, निरंतर गोष्ठियां चलती हैं और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही भारत सरकार के साथ उनका सतत संवाद बना रहता है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8 से बढ़कर लगभग 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है। परिणाम बताते हैं कि हम इससे भी बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

सीएम ने कहा कि मेरा मानना है कि आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 41-42 प्रतिशत था। समय के साथ इसका योगदान घटता गया। यदि कृषि व मैन्युफैक्चरिंग के बीच बेहतर समन्वय हो, तो विकास की गति और तेज हो सकती है। वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान अब भी लगभग 15झ16 प्रतिशत के आसपास है, जबकि कृषि का हिस्सा घटकर लगभग 20झ21 प्रतिशत तक सीमित रह गया। अब आवश्यकता है कि कृषि को वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए नए प्रयासों को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने तथा प्रभावी ढंग से विस्तार देने की आवश्यकता है।

निर्णायक भूमिका निभा सकती है तकनीक

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आज के दौर में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करवाए हैं। उदाहरण के तौर पर, वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, जो बेहतरीन परिणाम दे रहा है। यहां से नई-नई किस्में विकसित की गई हैं। अलग-अलग एग्रो-क्लाइमेटिक जोन के अनुसार कौन-सी किस्म उपयुक्त होगी, कौन-सी तकनीक अपनाई जानी चाहिए, क्वालिटी सीड किस प्रकार उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ये सभी परिणाम अब स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं।

उन्होंने प्रसन्नता जताई कि कुछ क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन 100 कुंतल तक पहुंच गया है, जो पहले 50झ60 कुंतल तक सीमित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल नीनो के कारण गेहूं और उद्यान फसलों, विशेष रूप से आम पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन यह एक सतत चुनौती है। इसके बावजूद, लागत कम करके उत्पादन बढ़ाना, समय पर अच्छे बीज उपलब्ध कराना, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के उपयोग को कम करते हुए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए अनुकूल वातावरण

मुख्यमंत्री ने बाराबंकी के प्रगतिशील किसान पद्म पुरस्कार से सम्मानित रामशरण वर्मा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि गत वर्ष मुझे उनके खेत पर ह्यविकसित कृषि अभियान' के तहत जाने का अवसर मिला। यदि कोई रामशरण वर्मा से उनकी शैक्षिक योग्यता पूछता है, तो वह स्वयं को ह्लदसवीं फेलह्व बताते हैं, लेकिन खेती में उनकी दक्षता और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग अत्यंत प्रेरणादायक है। वह कम लागत में अधिक उत्पादन करने का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की योजनाओं का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुझे विभिन्न जनपदों के खेतों में जाने का अवसर मिला, देखा कि जहां पहले किसान वर्ष में केवल एक फसल लेते थे, अब वहां तीन-तीन फसलें ली जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश की 85-86 प्रतिशत भूमि सिंचित है, बेहतर कनेक्टिविटी है और किसानों को 10-12 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। इन सब कारणों से कृषि के लिए अनुकूल वातावरण बना है।

'गद्दारों को माफ नहीं करेगा पंजाब', राघव चड्ढा के इस्तीफे पर मनीष सिसोदिया ने लगाए संगीन आरोप

(जीएनएस)।

आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी के आदर्शों से भटकाव का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। उनके साथ 7 अन्य सांसदों ने भी अअढ छोड़ने का ऐलान किया है।

इस घटनाक्रम पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे पंजाब के लोगों और कार्यकताओं के साथ 'बड़ी गद्दारी' करार दिया है। सिसोदिया के आरोपों ने इस दलबदल को पूरी तरह से भावनात्मक और नैतिक लड़ाई बना दिया है।

सिसोदिया का 'गद्दारी' वाला तीखा हमला

मनीष सिसोदिया ने बेहद कड़े शब्दों में राघव चड्ढा और उनके साथियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के हजारों कार्यकर्ता गुजरात और अन्य राज्यों में अपनी जान जोखिम में डालकर संघर्ष कर रहे हैं, तब कुछ नेताओं ने अपनी निष्ठा का सौदा कर लिया। सिसोदिया के अनुसार, यह सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि उन कार्यकताओं के खून-पसीने के साथ धोखा है जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। उन्होंने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया।

लालच और डर के आगे घुटने टेकने का आरोप

सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जो नेता आज बीजेपी के सामने झुक गए हैं, उन्होंने ऐसा किसी विचारधारा के कारण नहीं, बल्कि अपनी 'निजी मजबूरियों', 'डर' और 'लालच' की वजह से किया है। उनका इशारा साफ था कि जांच एजेंसियों या सत्ता के दबाव में आकर ये नेता टूटे हैं। सिसोदिया का मानना है कि पार्टी ने जिन लोगों को सबसे ज्यादा मान-सम्मान दिया, उन्होंने ही मुश्किल घड़ी में पार्टी का साथ छोड़कर अपनी कमजोरी और स्वार्थ का परिचय दिया है।

पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ीं! गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ठुकराई अग्रिम जमानत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार 24 अप्रैल को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

इस फैसले के बाद पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

अब धरातल पर उतर रहे कृषि के शोध, किसानों में उत्साह दिखा - सीएम योगी

आठ फीसदी कृषि विकास दर 18 प्रतिशत पर पहुंची

अंबेडकरनगर, (जीएनएस)। क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश के किसानों में उत्साह है। पहली बार कृषि इनोवेशन धरातल पर उतरा था। लैब के शोध को लैंड तक पहुंचाया गया।

लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग समस्या और समाधान हैं। पिछले साल खेती की बात खेत में कार्यक्रम चलाया गया। उसका फायदा मिला है। किसानों में उत्साह दिखा। पहली बार कृषि इनोवेशन धरातल पर उतरा था। लैब के शोध को लैंड तक पहुंचाया गया। यह बड़ा काम हुआ है। इसे आगे बढ़ाना होगा। हमारे पास सब है। बस नेतृत्व देना है। यह भारत सरकार की पहल सराहनीय है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है पहले नीतियां बनती थीं और कागज पर सब हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। हमें शासन की योजना के बारे में किसानों को अवगत कराना है। वर्ष 2017 में 69 कृषि विज्ञान केंद्र थे। वे बंदी के कगार पर थे। जवाबदेही नहीं थी। कृषि मंत्री ने बताया कि भारत सरकार नए कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती है लेकिन उस वक्त नहीं लिया गया। हमने लिया। अब हर कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। आठ फीसदी कृषि विकास दर 18 प्रतिशत पर पहुंची है। कृषि और उत्पादन में समन्वय हो तो विकास में गति मिलती है। कृषि में हमारा शेयर 20 फीसदी तक है। अब नया प्रयास हो रहा है।

उन्होंने कहा कि तकनीक निर्णायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई इंटरनेशनल सेंटर उपलब्ध कराए हैं। ये बेहतरीन परिणाम दे रहे हैं। समय पर बीज मिल गया तो उत्पादन बढ़ सकता है। यूपी में कई स्थानों पर 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हुआ है। उद्यान में आम की फसल प्रभावित हुई है। फिर भी लगत कम करके उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा।

उन्होंने बाराबंकी के राम शरण वर्मा का उदाहरण दिया। बोले कि ये 10वीं फेल हैं लेकिन वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। इस किसानों को चिन्हित करना होगा। उनके अनुभव दूसरे किसानों को बताना होगा। कुछ किसान तीन से चार फसल लेते हैं। इसे दूसरे किसानों को बताना होगा।।

मुख्यमंत्री ने कहा है 10 से 12 घंटे बिजली दे रहे हैं। पहले किसान को कुछ बताते नहीं थे। अब जागरूकता आई है। तीसरी फसल ले रहे हैं। ये जागरुकता से संभव हुआ।। इटावा, ओरैया और कानपुर देहात के किसान तीन फसल ले रहे हैं। मक्का प्रति एकड़ एक लाख कमा रहे हैं। अब किसान को भरोसा है कि उसकी पहल बेकार नहीं जाएगी। गेहूं 425 लाख मीट्रिक टन अकेले कर रहे हैं। आलू 245 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। ये रिकॉर्ड है यूपी के नाम।

उन्होंने कहा कि यूपी ने सब्जी से लेकर फल में छलांग लगाई है। पोटैटो सेंटर मिला है जो जल्द ही शुरू होने वाला है।

152 में 110 सीटें जीतेगी भाजपा, घुसपैठ मुक्त बनेगा बंगाल', बंपर वोटिंग के बाद बोले अमित शाह

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (इखढ) के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि भाजपा की सरकार 4 मई के बाद बंगाल में बनने जा रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा 152 से 110 सीटें जीत सकती है। 16 जिलों की 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ।

अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और 4 मई के बाद राज्य की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो सकता है। शाह का दावा है कि बंगाल की जनता ने इस बार 'परिवर्तन' के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है और 4 मई को नतीजे आते ही ममता बनर्जी की सरकार की विदाई तय है। 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ। इनमें से 52 सीटों पर तो वोटिंग का प्रतिशत 92.88% तक पहुंच गया।

अमित शाह ने अपनी चुनावी रणनीति और फीडबैक के आधार पर एक बड़ा आंकड़ा पेश किया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा ने जो आंतरिक आकलन किया है, उसके मुताबिक पार्टी 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है।

अमित शाह बोले,

"बंगाल की जनता ने पहले चरण में ही अपना भविष्य तय कर दिया है। कविगुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की भूमि ने विकास को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा चल रही है उसमें बंगाल भी जुड़ने वाला है, यह मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है। दीदी जाने वाली है, भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। 152 में से 110 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतने जा रही है, इसका अर्थ है कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद हम प्रचंड बहुमत से शुद्ध रूप से भाजपा सरकार बनाने वाले हैं।" अमित शाह ने कहा, "बंगाल की जनता ने पहले ही चरण में अपना भविष्य तय कर लिया है। दूसरे चरण के मतदान के बाद राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित है।" उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे पुराने डरावने चुनावों को भूल जाएं और बंगाल के सुनहरे भविष्य के लिए निडर होकर मतदान करें।

अमित शाह ने कहा, "राज्य में सत्ता विरोधी माहौल काफी मजबूत है और पिछली बार भी जनता में बदलाव की भावना दिखाई दी थी। हालांकि, उस चुनाव में वोटिंग पूरी तरह निष्पक्ष और डरमुक्त माहौल में नहीं हो पाई थी। कई जगहों पर बूथ कब्जाने और विपक्षी कार्यकर्ताओं को मतदान से रोकने जैसी घटनाएं सामने आई थीं। उन्होंने कहा कि इस बार मतदाता सूची की साफ-सफाई की गई है, फर्जी नाम हटाए गए हैं और प्रशासन, पुलिस, केंद्रीय बलों के साथ चुनाव आयोग ने मिलकर सुरक्षित और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने की कोशिश की है।"

महिलाओं ने तोड़े रिकॉर्ड: आधी आबादी का 'ममता' से मोहभंग?

इस चुनाव की सबसे बड़ी हाईलाइट महिला मतदाताओं की भागीदारी रही है। आंकड़ों के अनुसार, बंगाल में पुरुषों (90.92%) के मुकाबले महिलाओं ने 92.69% वोट डालकर एक नया इतिहास रच दिया है। वहीं, ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी 56.79% मतदान कर अपनी सक्रियता दिखाई है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में महिला वोटर हमेशा से ममता बनर्जी का मजबूत किला रही हैं। लेकिन शाह के चेहरे की मुस्कान बताती है कि भाजपा को लगता है कि इस बार महिलाओं का यह 'बंपर वोट' सुरक्षा और विकास के नाम पर भगवा खेमे में गिरा है।

अमित शाह ने कहा, "अमित शाह ने कहा, "बंगाल की मुख्यमंत्री यह अफवाह फैला रही हैं कि अगर बंगाल में भाजपा आई तो बाहरी लोग शासन करेंगे, मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा, बंगाली मीडियम में पढ़ा-लिखा और बंगाली भाषी होगा।

गौरंगो बिस्वास को लगाया गले, नाव वाले मोहम्मद इफ्तिखार को भी दे दिया मंत्र, पीएम मोदी ने दोनों को क्या दिया?

पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से चौंका दिया। पीएम मोदी ने सुबह-सुबह हुगली नदी के किनारे सैर की। इसके बाद बोट में बैठ विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की कैमरे से तस्वीरें भी खींची।

कोलकाता, (जीएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम दौरे में 19 अप्रैल को झालमुड़ी खाकर चौंका दिया था। शुक्रवार को कोलकाता की सुबह भी सरप्राइज के साथ हुई। पीएम मोदी क्या करने वाले हैं इसकी किसी को भनक नहीं लगी। पीएम मोदी ने हाथ में कैमरा लेकर हुगली घाट पर नाव की सवारी की। उन्होंने विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें भी खींची। पीएम मोदी ने हुगली नदी को पश्चिम बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ बताया। पीएम मोदी ने कहा कि

मां गंगा का बंगालियों के जीवन में एक विशेष स्थान है और इसका जल एक प्राचीन सभ्यता की भावना को अपने साथ समेटे हुए है। पीएम मोदी गौरंगो बिस्वास की नाव में बैठे। उन्होंने गौरंगो बिस्वास को न सिर्फ बोट राइड के लिए 1000 रुपये किराए के तौर दिए तो वहीं गले भी लगाया।

राइड के लिए सात नावें किराए पर लीं

पीएम मोदी का यह दौरा इतना गोपनीय था कि किसी को ज्यादा पता ही नहीं चल पाया। लोगों ने जब पीएम मोदी को हुगली को घाट पर होने के बारे में पता चला तो वे चकित रहे गए। हुगली घाट पर नावों का बिजनेस करने वाले बिहार के मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने इसकी पुष्टि की। पीएम की राइड के लिए मोहम्मद इफ्तिखार अहमद की सात नावें किराए पर ली गई थी। पीएम मोदी के दौरे की तस्वीरें खूब चर्चा में आ गई हैं। पीएम मोदी ने जब झारग्राम में झालमुड़ी खाई थी तो वह उसे इंटरनेट पर बहुत चर्चा मिली थी।

हाथ में डीएसएलआर कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव के बीच व्यस्त कार्यक्रम के बीच

समय निकालकर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे समय बिताया और बंगाल के विकास का वादा दोहराया.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे और वहां हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया. इस दौरान उन्होंने मां गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और बंगाल के लोगों के लिए अपने संदेश साझा किए. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखा कि हर बंगाली के लिए गंगा का बहुत खास महत्व है.

जब मुख्यमंत्री योगी की फोटो लेने के लिए सांसद रवि किशन ने थामा मोबाइल, करते दिखे 'डायरेक्शन'

गोरखपुर , (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1055 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने ईको पार्क का भ्रमण किया। सांसद रवि किशन ने बेकार वस्तुओं से बने शेर के सामने उनकी फोटो खींची।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में 1055 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वह ईको पार्क का भ्रमण कर रहे हैं और सांसद रवि किशन वेस्ट (बेकार की वस्तुओं) से बने एक शेर की कलाकृति के सामने अपने फोन से उनका फोटो लेते दिख रहे हैं। वह एक अच्छे पोज के लिए सीएम योगी से आगे आने का भी आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं।

वैदिक मंत्र उपचार के बीच फीता काटकर लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईको पार्क का भ्रमण किया। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने उन्हें पार्क में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी।

इस दौरान नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री के समक्ष चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से यहां के पूर्व और वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक दृश्य भी प्रस्तुत किया।

पार्क का भ्रमण करने के दौरान सीएम योगी ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। ईको पार्क में वेस्ट से बनी कलाकृतियों को देखकर सीएम ने प्रसन्नता जताई और वेस्ट से ही बने शेर की कलाकृति के सामने फोटो खिंचवाई। इस दौरान सांसद रवि किशन ने अपना मोबाइल निकाला और फोटो लेने के लिए मुख्यमंत्री की शेर के साथ फोटो लेने के लिए फिल्मी तरीके से दिशा बताने लगे।

गोरखपुर शहर के प्रवेश द्वार पर कचरे को कंचन में बदल दिया नगर निगम ने

ईको पार्क के विकास के लिए नगर निगम की पूरी टीम की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने गोरखपुर शहर के प्रवेश द्वार पर कचरे को कंचन में बदलने का काम किया है। 2.26 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण कर बनाया गया ईको पार्क पूरे परिवार के लिए पिकनिक स्पॉट और बेहतरीन पर्यटन स्थल बन गया है। यहां पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क है। योग और ध्यान की क्रिया के लिए व्यक्ति यहां आराम से बैठ सकता है। उन्होंने कहा कि यह जो परिवर्तन आया है, वह गोरखपुर के विकास का मजबूत विश्वास और यहां की टीम के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।

कचरा में हीरा खोज लेते हैं सीएम योगी : रविकिशन

कार्यक्रम में सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि सीएम योगी का विजन अद्वितीय है। वह कचरा में हीरा खोज लेते हैं। वह असंभव को संभव कर देते हैं। उनकी सोच से एकला बांध पर जहां गटर था, वहां अब रोजगार मिलेगा। यहां फिल्मों की शूटिंग भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर विकास की नजीर पेश कर रहा है। जहां बीमारी पहचान बन गई थी, वहां अब विकास का विश्वास है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में मित्सुई प्रबंधन से की व्यापक निवेश पर चर्चा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में मित्सुई प्रबंधन से की व्यापक निवेश पर चर्चा

उत्तर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के पहले दिन वैश्विक निवेश संवाद की मजबूत शुरूआत की। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जापान की अग्रणी वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी लिमिडेट के प्रबंधन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में परिवर्तनकारी निवेश अवसरों को तलाशने का औपचारिक आमंत्रण दिया।

सीएम योगी ने चार प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को किया रेखांकित

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, जापान में आज बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चार प्रमुख

क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर, बायो-एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं दूसरी आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के तहत आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश पर चर्चा हुई। तीसरा सेक्टर सेमीकंडक्टर का रहा, जिसमें चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का विस्तार प्रमुख रहे। वहीं चौथा सेक्टर डेटा सेंटर रहा, जिसमें हाइपर-स्केल डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी हब जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर गहन विमर्श हुआ।

भारत-जापान आर्थिक सहयोग को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने मित्सुई प्रबंधन को दीर्घकालिक साझेदारी के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत-जापान आर्थिक सहयोग को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के साथ-साथ उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर्स के कारण निवेशकों के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री योगी ने राज्य सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और परिणामोन्मुख वातावरण उपलब्ध कराता है।

गौतमबुद्धनगर में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा अभियान, डीएम मेधा रूपम ने किया मेडिकल कैंप्स का निरीक्षण

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में श्रमिकों के लिए 25 स्थानों पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में स्वास्थ्य जांच, दवाएं, आंखों, दंत और महिला रोग सुविधाएं दी गईं जिसका हजारों श्रमिकों ने लाभ उठाया।

गौतमबुद्धनगरः (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशन में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद गौतमबुद्धनगर में स्वास्थ्य विभाग, निजी अस्पतालों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 25 स्थानों पर व्यापक मेडिकल कैंप/मेला आयोजित किया गया। गौतमबुद्धनगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने अंबेडकर भवन, सूरजपुर में आयोजित मेडिकल कैंप का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया।

'मेडिकल कैंपों में आधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध'

श्रमिकों ने मेडिकल कैंपों की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा, 'आज यहां पर जो मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है, इसी प्रकार के विस्तृत मेडिकल कैंप आगे भी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए लगाए जायेंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में

आयोजित मेडिकल कैंप में पहुंचकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों एवं एनजीओ के सहयोग से आयोजित कराए जा रहे हैं मेडिकल कैंपों में आधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं।'

'महिला श्रमिकों के लिए ब्रेस्ट स्कैनिंग जैसी सुविधाएं'

जिलाधिकारी ने आगे कहा, 'विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए मैमोग्राफी एवं ब्रेस्ट स्कैनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही डेंटल के लिए भी पूर्ण सेटअप उपलब्ध है, जिसमें छोटी-छोटी कैविटी भरने से लेकर आवश्यक उपचार तक की सुविधा तथा एक्स-रे जैसी जांच सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी। आंखों की जांच से लेकर मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन तथा मुफ्त चश्मा वितरण की व्यवस्था भी मेडिकल कैंपों में उपलब्ध कराई जा रही है।'

मजदूरों के लिए अभियान में क्या है खास?

श्रमिकों के स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।

प्रशासन का लक्ष्य है कि उद्योगों में काम करने वाले करीब 12 लाख श्रमिकों को आधुनिक और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। गौतमबुद्धनगर की 8000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज के श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा।

1 मई को होने वाले बड़े स्वास्थ्य कैंप के लिए जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। आज से ही अलग-अलग उद्योगों में रोजाना स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, जिनका रोस्टर तैयार कर लिया गया है। साथ ही उद्योगों के पास के 25 रिहायशी इलाकों में भी कैंप लगाए जा रहे हैं।

70 से ज्यादा निजी अस्पताल सरकारी अस्पतालों के साथ मिलकर श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं आसान बना रहे हैं।

इस अभियान में आधुनिक सुविधाओं से लैस विशेष बसें भी शामिल हैं, जिनमें मैमोग्राफी, एक्स-रे, डेंटल चेयर, डेंटल सर्जरी और अन्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं श्रमिकों के घर के पास या उनके कार्यस्थल तक पहुंचाई जाएंगी।

एक बड़ा कदम यह है कि 1 मई को 22 बड़े निजी अस्पताल श्रमिकों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर तक का इलाज मुफ्त में देंगे।

गौतमबुद्धनगर में इस तरह की पहल पहली बार की जा रही है, जो काफी सराहनीय है।

कई उद्योगों में बच्चों के लिए क्रेच (देखभाल केंद्र) खोले जाएंगे और वहीं पर छोटे क्लीनिक भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही हर उद्योग में नियमित स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे।

श्रमिकों की रहने की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।

उरफ के तहत कई एनजीओ और उद्योग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी निगरानी जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

श्रमिकों से मेडिकल कैंप्स का लाभ उठाने की अपील

जिलाधिकारी ने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा, 'मेडिकल कैंपों में अपने परिवार, बच्चों तथा बुजुर्गों को भी साथ लाकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठाएं। बच्चों के लिए इसका लाभ मिलना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि भीषण गर्मी के बीच लगातार कार्य करने से शिक्षकों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ रहा है। ग्रीष्मावकाश शिक्षकों के लिए विश्राम और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण समय होता है, जिसे ड्यूटी में लगाने से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को उनके सेवा अभिलेख में नियमानुसार अर्जित अवकाश जोड़ा जाए। साथ ही आश्वस्त किया गया है कि शिक्षक हमेशा राष्ट्रहित के कार्यों के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनके वैधानिक अधिकारों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।

गर्मी की छुट्टियों में जनगणना ड्यूटी से भड़के शिक्षक, सीएम योगी से कर दी ये मांग

शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी के बदले अर्जित अवकाश की मांग।

ग्रीष्मावकाश में कार्य करने से स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर।

वित्तीय नियमों के तहत ईएल देने का प्रावधान लागू हो।

लखनऊ। (जीएनएस)। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के दौरान ड्यूटी के बदले अर्जित अवकाश (इएल) देने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों के हितों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है।

उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के निदेर्शानुसार राष्ट्रीय जनगणना-2026 का कार्य जारी है, जिसमें परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षक इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरी निष्ठा से तैयार हैं, लेकिन यह कार्य

ग्रीष्मावकाश के दौरान कराया जा रहा है, जो उनके वैधानिक अवकाश का समय होता है।

वित्तीय नियमों के अनुसार यदि किसी वेकेशन विभाग के कर्मचारी से अवकाश के दिनों में कार्य लिया जाता है, तो उसे बदले में अर्जित अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को भी

गोरखपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बोलीं- सीएम योगी के राज में रोड क्राइम बंद, आंख उठाने की नहीं किसी में हिम्मत

आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने नारी वंदन अधिनियम बिल पर विपक्ष को घेरा. कहा, महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी.

गोरखपुर : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में रोड क्राइम की घटना घटी है. ऐसी घटना को अंजाम देने की अब कोई भी अपराधी हिम्मत नहीं करता. लड़कियां रात को 12 बजे या 1 बजे भी सड़क पर जा रही हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखे. 2017 से पहले क्या हाल था, यह सब जानते हैं. अब बेटियां सुरक्षित होकर स्कूल और नौकरी पर जा सकती हैं.

बबिता चौहान ने शुक्रवार को गोरखपुर में समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि महिला आयोग हर बार किसी न किसी नए विषय पर चिंता करता है. हमने आज अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञों को

बुलाया था. आज 'एआई' (अक) पर बहुत बातें हुई और 'मानव तस्करी' पर भी चर्चा हुई. जब हम साथ बैठते हैं, तो कुछ न कुछ नया निकलकर आता है जिस पर हम काम करते हैं.

राज्य महिला आयोग ने की समीक्षा बैठक.

उन्होंने कहा, महिला आयोग 24 घंटे सक्रिय रहता है. हमारे पास व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और टोल-फ्री नंबर हैं, ताकि कोई भी कभी भी कॉल कर सके और हम तत्काल कार्रवाई कर सकें. उन्होंने कहा, आजकल 'डिजिटल अरेस्ट' के बहुत मामले आ रहे हैं, जिसमें अच्छे-खासे अनुभवी लोग भी फंस जाते हैं. मैं कहना चाहूंगी कि इन चीजों से बचें और सतर्क रहें. सबसे जरूरी बात अपनी बातों को छिपाना छोड़ें और बताना शुरू करें.

राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जो महिला बिल कांग्रेस के शासनकाल 1996 से पास नहीं हो सका, उसे मौजूदा सरकार ने पास करने का पुनः प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने इस बिल का समर्थन नहीं किया. सारी महिलाओं को बेवकूफ बनाने का कार्य किया गया है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सम्बोधन को पुनः विपक्षियों को सुनना चाहिए. हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास है और जो विपक्ष ने किया है उसको लेकर नारी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.

देश की नारी जो दुर्गम क्षेत्र में है उन सभी पर प्रभाव पड़ा है और सभी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़े. इस बिल को लेकर नारियों में जिस तरीके से आक्रोश है, गुस्सा है निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और विपक्ष को इसकी चिंता करनी पड़ेगी.

बिकरू कांड वाली 'खुशी' अब बनेगी वकील! बदनामी के 6 साल बाद गाड़े सफलता के झंडे

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने गुरुवार (23 अप्रैल) को कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल के नतीजों में जहां एक बार फिर बेटियों का दबदबा रहा, वहीं कानपुर के चर्चित बिकरू कांड की आरोपी रही खुशी दुबे ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी इच्छाशक्ति का लोहा मनवाया है।

तमाम मानसिक दबाव और कानूनी उलझनों के बीच खुशी दुबे ने इंटरमीडिएट की परीक्षा 61 फीसदी अंकों के साथ पास कर ली है। आइए जानतें हैं खुशी दुबे ने अपनी सफलता पर क्या कहा और इस साल यूपी बोर्ड का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा?

बिकरू कांड के बाद लंबे समय तक कानूनी कार्यवाही और मानसिक तनाव का सामना करने वाली खुशी दुबे ने अपनी इस सफलता को संघर्ष का परिणाम बताया है। खुशी ने बताया कि उनके लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ कोर्ट-कचहरी के चक्कर और दूसरी तरफ मां की खराब तबीयत, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया।

अब क्या है खुशी का अगला लक्ष्य?

खुशी का लक्ष्य अब कानून की

पढ़ाई (LLB) कर एडवोकेट बनना है, ताकि वह न्याय व्यवस्था के माध्यम से समाज की सेवा कर सकें।

शादी के महज तीन दिन बाद मिली बदनामी

दरअसल, पनकी रतनपुर की रहने वाली खुशी तिवारी के जीवन में 29 जून 2020 को अमर दुबे से शादी के बाद एक बड़ा मोड़ आया। शादी के महज तीन दिन बाद ही दो जुलाई 2020 को कुख्यात बिकरू कांड हुआ, जिसमें विकास दुबे और अमर दुबे ने पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया। इस हिंसक घटना में सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। पुलिस कार्रवाई में खुशी के पति अमर दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जिसके बाद खुशी को हत्या की साजिश और विस्फोटक अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं में आरोपित बनाया गया था।

अब कहां है खुशी दुबे?

पांच जुलाई 2020 को जेल जाने के बाद खुशी को कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा। शुरूआती दौर में परिजनों ने उनके नाबालिग होने का दावा किया, जिसकी पुष्टि होने के बाद उन्हें बाराबंकी बाल सुधार गृह भेजा गया। करीब 28 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद, 4 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और 20 जनवरी को उनकी रिहाई हो सकी। जेल से बाहर आने के बाद खुशी ने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की ठानी और पढ़ाई को अपना हथियार बनाया, जिसका रिजल्ट अब उनके शानदार परीक्षा परिणाम के रूप में सामने आया है।

12वीं में शिखा और 10वीं में कशिश ने किया टॉप

यूपी बोर्ड 2026 के नतीजों में सीतापुर जिले का बोलबाला रहा। 12वीं (इंटरमीडिएट) में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60% अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं, 10वीं (हाईस्कूल) में भी सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा 97.83% अंकों के साथ संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर रहीं। छात्राओं ने इस साल भी लड़कों को पीछे छोड़ते हुए टॉप तीन स्थानों पर कब्जा जमाया है।

ईरान पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा? भारत के बाद चीन ने भी नागरिकों को तुरंत भागने का दिया आदेश

(जीएनएस)।

ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत के बाद अब चीन ने भी अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर उन्हें तुरंत ईरान छोड़ने या सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। दूतावासों की इन चेतावनियों ने युद्ध की आहट को और तेज कर दिया है।

लोग डरे हुए हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी तबाही होने वाली है? एयरस्पेस की अनिश्चितता और सीमा पर बढ़ती हलचल यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिन इस क्षेत्र के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

चीन की सख्त चेतावनी

भारत के नक्शेकदम पर चलते हुए अब चीन ने भी अपने नागरिकों को ईरान से बाहर निकलने की सलाह दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि वहां सुरक्षा हालात बहुत खराब हैं और स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। चीन ने अपने लोगों को संवेदनशील और सैन्य ठिकानों से दूर रहने की हिदायत दी है। साथ ही, नए

लोगों को ईरान की यात्रा न करने के लिए कहा गया है। चीन का यह कदम बताता है कि बीजिंग को बड़े हमले का अंदेशा है।

भारत ने पहले ही दी थी सलाह

भारत सरकार ने करीब 24 घंटे पहले ही अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से ईरान की यात्रा टालने और वहां रह रहे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित रास्तों से निकलने या दूतावास के संपर्क में रहने को कहा था। भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि युद्ध छिड़ने की स्थिति में वहां फंसे लोगों को निकालना काफी मुश्किल हो सकता है।

क्या जंग अब तय है?

ईरान के हवाई क्षेत्र का बार-बार बंद होना और देशों का अपने नागरिकों को वापस बुलाना, ये सामान्य संकेत नहीं हैं। हालांकि किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर युद्ध का एलान नहीं किया है, लेकिन सीमाओं पर बढ़ती सैन्य तैनाती और इजरायल के साथ बढ़ती तनातनी 'दूसरे दौर की भीषण जंग' की तरफ इशारा कर रही है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है।

आम जनता पर बढ़ता खतरा

अगर ईरान में युद्ध छिड़ता है, तो इसका असर सिर्फ वहां रहने वाले चीनियों या भारतीयों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन तक सब कुछ प्रभावित होगा। सबसे बड़ा खतरा उन मासूम लोगों पर है जो इस तनाव के बीच वहां फंसे हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की अपील की जा रही है, लेकिन जमीनी हालात को देखकर लगता है कि शांति की गुंजाइश फिलहाल बहुत कम बची है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

भारत ने ट्रंप की निंदनीय टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे से कम समय में ही यूटर्न लेते हुए बृहस्पतिवार को भारत की तारीफ की और कहा कि इस देश का नेतृत्व एक बहुत अच्छा दोस्त कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिन यानि बुधवार को ट्रंप ने अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकेल सेवेज के पाडकास्ट से एक नस्लवादी टिप्पणी को रिपोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने भारत, चीन और अन्य देशों को हेलहोल मतलब कि नरक का द्वार बताया था। दरअसल अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए अपने नस्लवादी बयान में सेवेज ने आरोप लगाया था कि इन दो एशियाई देशों के लोग अमेरिका में नौवें महीने बच्चा पैदा करने आते हैं और यह कानून उन्हें तुरन्त अमेरिका का नागरिक बना देता है। ट्रंप ने सेवेज की पाडकास्ट 'सेवेज नेशन' की ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तर्कों की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन जैसे ही ट्रंप की आलोचना सोशल मीडिया पर शुरू हुई अमेरिकी लोकतांत्रिक संस्थाओं का माथा ठनका कि उनके राष्ट्रपति ने क्या नासमझी कर दी। इसी व्रम में स्टेट डिपार्टमेंट के निर्देश पर नई दिल्ली स्थित अमेरिकी राजदूतावास के प्रावक्ता ने बताया कि रिपब्लिकन पाटा के नेता ने भारत के बारे में गर्मजोशी से बात की है और इसे महान राष्ट्र बताया और कहा कि भारत के नेता के साथ उनकी खास दोस्ती है। खुद ट्रंप ने भी पलटी मारते हुए कहा कि "भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है।" बहरहाल भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस निदनीय टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि भारत की वूटनीतिक परिपक्वता इतनी अधिक है कि वह एक व्यक्ति की वजह से अमेरिका जैसे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्राति अपने संबंधों को कमजोर नहीं कर सकता। इसलिए विदेश मंत्रालय के प्रावक्ता ने मात्र इतना ही कहा कि भारत सरकार संपूर्ण बयान का अध्ययन कर रही है। भारत जानता है कि ट्रंप एक अविश्वसनीय चरित्र के व्यक्ति हैं इसलिए संबंधों के स्थापित एवं मजबूती के लिए इस व्यक्ति को नजरदांज करना ही उचित है। यही हालत स्टेट डिपार्टमेंट की भी है। वह इस बात को महसूस करता है कि आज जब अमेरिका को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है तो उनका राष्ट्रपति अल्लबल्ल बोल रहा है। लब्बोलुआब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की हर बकवास की खबर बनने से भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के प्राभावित होने से बचाने के लिए अमेरिकी संस्थाओं के साथ मिलकर बड़ी ही सावधानी एवं वुशलता से वूटनीतिक परिचय देना होगा। वुल मिलाकर ट्रंप को टालने में ही भलाई है।

भारत की आंतरिक सुरक्षा को नोएडा के श्रमिकों को भड़काने जैसी हरकतों से चुनौती देता पाकिस्तान

(जीएनएस)।

भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए अब वह नोएडा के श्रमिक आंदोलन जैसे हिसक प्रदर्शन देश में करने की योजना बना रहा है।

स्थिति की गंभीरता इसी से सिद्ध होती है कि नोएडा के श्रमिकों के आंदोलन के लिए पाकिस्तान ने पामि बंगाल से एक दल और जवाहरलाल नेहरू यूनिर्वसिटी से छात्रों को बुलाया जिससे यह आंदोलन उग्र और हिसक बन सके।

गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 13 अप्रैल को हुई हिसा में पाकिस्तानी साजिश सामने नजर आई है।

नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों ने 13 अप्रैल को वेतन वृद्धि के लिए प्रदर्शन किया। जिसको पुलिस ने श्रमिकों को समझकर 12:00 बजे तक शांत कर दिया था। परंतु इसके बाद पाकिस्तान स्थित एक्स हैंडल प्राईड इंडिया और मीर इलियास आईएनसी नाम के अकाउंटों से झूठी पोस्ट की गईं की उपरोत्त श्रमिक प्रदर्शन में 20 लोग मारे गए हैं तथा 99 घायल हुए है। इस पोस्ट के द्वारा शांत हुए श्रमिक दोबारा भड़क गए और वह सड़कों पर आ गए जहां पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इन अकाउंटों के इस प्रकार के भड़काऊ पोस्टो से सीधा पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। इन अकाउंटों की पोस्ट के बाद मजदूर संगठन से जुड़े रूपेश राय, मनीष चौधरी और आदित्य आनंद ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से श्रमिकों को भड़काया। इसके बाद श्रमिकों ने उग्र प्रदर्शन करके पूरे नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को इनमें तोड़फोड़ कर के बंद कराकर तनाव पैला दिया।

देश की राजधानी के नजदीक होने कारण पुलिस ने शीघ्रता से कार्यवाही करते हुए स्थिति को काबू में किया। बाद में नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस प्रकार के प्रदर्शनों से पाकिस्तान की वुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई देश के औद्योगिक शहरों में अशांति पैलाकर देश के औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करना चाहती है। इन हर हरकतो से पाकिस्तान भारत सरकार के विरुद्ध जन आव्रोश पैलाने के बहाने ढूंढता रहता है। इसी कारण भारत में उसके एजेंट अक्सर सरकार की नीतियों को सांप्रदायिक रंग देकर देश की मुस्लिम आबादी में असंतोष पैलाकर अराजकता और सरकार विरोधी माहौल बनाने की कोशिश करते है। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून देश में घुसपैठियों को देश की नागरिकता से दूर करने तथा अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए पास किया गया था।

परंतु पाकिस्तान के एजेंटों ने दिल्ली के मुस्लिम बहुल क्षेत्रओ में दुष्प्रचार किया कि इस कानून के द्वारा मुसलमानों को भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा।

इस प्रचार के परिणाम स्वरूप दिल्ली के मुस्लिम बहुल क्षेत्र शाहीन बाग में मुस्लिम समाज ने सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन पूरे 101 दिन चला और इसकी समाप्ति सांप्रदायिक दंगों में हुई। वह भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली दौरे पर थे जिसके कारण पूरे विश्व की प्रेस दिल्ली में एकत्रित थी जिसने इन दंगों के बारे में पूरी दुनिया में खबर पैलाकर भारत की छवि को विश्व पटल पर बिगाड़ने की कोशिश की। बाद में जांच में पाया गया कि इस धरने में रोजाना हिस्सा लेने वालों को

आईएसआई के इशारे पर बब्बर खालसा के एजेंट पैसा देकर बुलाते थे जिसके लिए धन हवाला के जरिए एजेंटों के पास पहुंच रहा था। इसी के साथ पाया गया कि पूवा दिल्ली की वुछ कॉलोनीयों में आईएसआई के एजेंटों ने दंगों की तैयारी पहले से कर ली थी। जिसके कारण पुरानी दिल्ली की कॉलोनीयो में ये देंगे लंबे समय तक चले। इस प्रकार आईएसआई ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन को निशाना बनाते हुए नोएडा जो उत्तर प्रदेश के उत्पादन का 10ट्ठ उत्पादन करता है कि मजदूरों को पाकिस्तान में स्थित अक्स हैंडलूम के द्वारा तरह-तरह की भड़काऊ पोस्टो द्वारा उत्तेजित करके उनसे हिसक प्रदर्शन करवाये जिसमें वुछ लोग मारे गए तथा काफी घायल हो गए।

आजादी के बाद से ही पाक सेना भारत में हर विघटनकारी तत्व को हर प्रकार की सहायता प्रदान करती आई है। 1970 से पहले उत्तर पूर्व के राज्यों नागालैंड और मिजोरम तथा अन्य राज्यों में देश विरोधी तत्व भारत से अलग होकर स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे।

उस समय बांग्लादेश पूवा पाकिस्तान था।

इसलिए तत्कालीन पूवा पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पूरी तरह सायि थी। इसी के कारण नागालैंड मूवमेंट के नेता जकौटो सेमा भारतीय कानून से बचने के लिए अक्सर पूवा पाकिस्तान में छुप जाता था। इसी प्रकार मिज़ो नेशनल प्रंट का ऑफिस ढाका और चिटगांव में था। जहां से यह प्रंट भारत विरोधी गतिविधियों बिना रोकटोक के चला रहा था। इसलिए नागालैंड और मिजोरम में काफी समय तक उपरोत्त संगठनों के द्वारा उत्तल-पुथल मचाई गईं। इन संगठनों ने इन राज्यों के विकास पर बुरा असर डाला जिसके कारण ये राज्य विकास में पिछड़ने लगे। परंतु अंत में भारतीय सेना तथा पुलिस ने स्थिति को काबू में करते हुए इन आंदोलन को शांत करते हुए स्थिति को सामान्य बनाया। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाक सेना ने अक्टूबर 1947 में ही कश्मीर पर हमला कर दिया था। क्योंकि उस समय तक इस राज्य का भारत में विलय नहीं हुआ था जिसके कारण महाराजा की सेना पाक सेना का मुकाबला नहीं कर सकी और पाक सेना श्रीनगर के करीब बारामुला तक आ गईं। इसी समय इस राज्य का भारत में विलय हो गया इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेणना शुरू किया परंतु उसी समय यह मसला संयुत्त राष्ट्र संघ में पहुंच गया जिसके बीच में आने के कारणअभी तक कश्मीर का वुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है जिसको पाक अधिवृत कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान की आईंएसआईं ने मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकी ग्रुप जैसे लश्करे-तैयबा, जैसे मोहम्मद और जम्मू कश्मीर लिबरेशन प्रंट इत्यादि तैयार किये और इन्हें कश्मीर में भारत से अलग होने के लिए आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए कहा।

इन गुटों ने काफी समय तक जम्मू कश्मीर में अशांति पैलाईं परंतु भारतीय सेना और वेंद्रीय सुरक्षा एजेंटीयों के द्वारा स्थिति को काबू में लाया गया। और आज यह राज्य पूरी तरह शांत है और विकास के रास्ते पर चल रहा है। इसी प्रकार 1971 के युद्ध में करारी हार मिलने के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना ने भारत के पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चलाकर पंजाब को भारत से अलग करने की कोशिश की। इसके लिए उसने खालिस्तानी तत्वों को हर प्रकार की सहायता और हथियार तथा गोला बारूद उपलब्ध कराया परंतु पंजाब की राष्ट्रवादी जनता के सहयोग और देश की सुरक्षा एजेंसियों तथा भारतीय सेना के द्वारा पंजाब की स्थिति को सामान्य बनाया गया। जिसके लिए भारतीय सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी कार्रवाईं करनी पड़ी।

जम्मू कश्मीर और पंजाब में नाकामी मिलने के बाद पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध खुले आम परोक्ष युद्ध के रूप में भारत के अन्य हिस्सों में हिस्सों मेंआतंकी गतिविधियां बढ़ा दिए। इनके द्वारा वह जगह-जगह सांप्रदायिक दंगेऔर विस्फोट और विस्फोट करके जनता में असुरक्षा और बका वातावरण पैदा करना चाहता है जिस देश की जनता का अपनी सरकार से विश्वास उठ जाए और देश में अशांति पैल जाए। इसी के अंतर्गत 2016 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए और ऐसे दंगे देश में जगह-जगह देखे गए। अब पाकिस्तान की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है क्योंकि इस समय भारत विश्व की एक आर्थिक महाशत्ति के रूप में 4 वे में स्थान पर स्थित है। वहीं पर पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था इतनी खस्ता हाल हो गईं है कि उसको अपना खर्च चलाने के लिए आईंएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ रहा है जिसके लिए वह अमेरिका की चाप लूसी हर स्थिति में कर रहा है।

भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को बिगड़ने केलिए अब वह नोएडा के श्रमिक आंदोलन जैसे हिसक प्रदर्शन देश में करने की योजना बना रहा है।

स्थिति की गंभीरता इसी से सिद्ध होती है कि नोएडा के श्रमिकों के आंदोलन के लिए पाकिस्तान ने पामि बंगाल से एक दल और जवाहरलाल नेहरू यूनिर्वसिटी से छात्रों को बुलाया जिससे यह आंदोलन उग्र और हिसक बन सके। साभार- कर्नल शिवदान सिंह (सेवानिवृत्त)

'पांच मिनट पहले पता चला कि पीएम मोदी आ रहे हैं': बोट मालिक को पीएम ने क्या दिया संदेश? जानें कैसे बुक की गई नाव

(जीएनएस)।

कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली नदी में नौका सैर की। जानकारी के अनुसार, इस दौरान पीएम मोदी की बोट के अलावा छह बोट और बुक की गई थी। पीएम मोदी की नाव के मालिक इफ्तिकार ने बताया कि तो उन्होंने बताया कि हम से एक ही बात बोलकर गए कि सभी मिल-जुलकर रहो, अच्छे से रहो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोलकाता के हुगली नदी में नौका विहार का आनंद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नौका में सैर किया, उसके अलावा छह अन्य नौकाएं भी बुक की गई थीं। प्रधानमंत्री ने जिस नाव में सैर किया उसके नाव के मालिक मोहम्मद शेख इफ्तिकार ने नाव की बुकिंग और पीएम मोदी से साथ अपने संवादा का अनुभव साझा किया है। बता दें कि, पीएम मोदी पिछले कई दिनों से विधानसभा चुनाव

के मद्देनजर राज्य का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार की सुबह उन्होंने नौका सैर की।

'पीएम मोदी के नाव के अलावा सात और नावें की गई थी बुक'

एएनआई से बात करते हुए नाव के मालिक इफ्तिकार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे केवल एक ही बात कही। उन्होंने सभी को मिलजुलकर और अच्छे से रहने का संदेश दिया। इस दौरान इफ्तिकार ने बताया कि आज सुबह एक व्यक्ति उनके पास आया और सात नौकाओं की मांग की। इफ्तिकार ने सोचा कि कोई खास व्यक्ति आ रहा है, इसलिए उन्होंने दाम बढ़ाने के बारे में सोचा। लेकिन उन्हें बताया गया कि ऐसा कुछ खास नहीं है और कोई बड़ा मामला नहीं है। उन्हें बताया गया कि कुछ दोस्त घूमने आएंगे और थोड़ी देर घूमेंगे। इस पर, जो सामान्य दरें होती हैं, उसी पर नौकाओं को बुक किया गया।

प्रधानमंत्री का आगमन और संदेश

इफ्तिकार आगे ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पहले सुबह की सैर पर निकले थे, इसके बाद वे रेल मार्ग से पानी घाट पहुंचे। फिर वहां से पैदल चलकर सीधे वे यहां आए और उन्होंने नौका सैर की। इफ्तिकार ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने नौका से उतरते समय सभी से अच्छे से रहने और मिलजुलकर रहने को कहा। उन्होंने कोई और बात नहीं की, केवल यही संदेश दिया।

ओमपुरी ने मेरी बहन की लाइफ बर्बाद कर दी', अन्नू कपूर ने बताया कड़वा सच, बोले- '4 महीने प्रेग्नेंट औरत संग'

(जीएनएस)।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा ऐसा किस्सा शेयर किया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने अपनी बहन के टूटे रिश्ते और उससे जुड़े दर्दनाक अनुभवों पर खुलकर बात की है। ये सिर्फ एक असफल शादी की कहानी नहीं है बल्कि भरोसे के टूटने, भावनात्मक आघात और एक पूरे परिवार के बिखरने की दास्तान है।

अन्नू कपूर की बहन को मिला दर्द और धोखा

अन्नू कपूर के इस खुलासे ने एक बार फिर दिवंगत अभिनेता ओम पुरी की निजी जिंदगी से जुड़े पुराने विवादों को चर्चा में ला दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अन्नू कपूर ने अपनी बहन के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है। उन्होनें बताया कि ये रिश्ता उनकी बहन के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ था, जिसमें उसे धोखा और विश्वासघात का सामना करना पड़ा था।

अन्नू कपूर ने ओम पुरी पर लगाए गंभीर आरोप

-अन्नू कपूर के मुताबित इस टूटे हुए रिश्ते ने न सिर्फ उनकी बहन की जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया था बल्कि पूरे परिवार को भी झकझोर कर रख दिया था। अन्नू कपूर ने कहा कि इस अनुभव ने उनकी बहन को भावनात्मक रूप से काफी नुकसान पहुंचाया था और उससे उबरना उसके लिए आसान नहीं था। सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में अन्नू कपूर ने ओम पूरी को एक असाधारण कलाकार बताया।

-अन्नू कपूर ने कहा- ओम पूरी एक बेहतरीन अभिनेता थे, उनके जैसा कोई नहीं था लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। वह किसी के पति बने और पति बनने के बाद उन्होंने एक महिला को धोखा दिया। वहीं से सब कुछ गलत हो गया और मैं उसी महिला का भाई हूं।

सीमा कपूर और ओम पुरी की दर्दनाक शादी और बेवफाई

-आपको बता दें कि अन्नू कपूर अपनी बहन सीमा कपूर का जिक्र कर रहे थे जिनकी शादी 1990 के दशक की शुरूआत में ओम पूरी से हुई थी। हालांकि ये रिश्ता कुछ ही महीनों में टूट गया था, जब सीमा को अपने पति ओम पूरी के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध के बारे में पता चला था।

-अन्नू कपूर ने बताया- जब मेरी बहन अपने पति से अलग हो रही थी तो वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी लेकिन इसके बावजूद ओम पुरी ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

-अन्नू कपूर ने आगे कहा- हालात इतने खराब हो गए थे कि गर्भपात होने के बाद मुआवजें के तौर पर मेरी बहन को सिर्फ 2500 रुपये देने की बात कही गई थी, जिसे उसने ठुकरा दिया था। ये पूरा घटनाक्रम मेरे लिए बेहद दर्दनाक और आघात पहुंचाने वाला था।

पहते रिश्ते के बाद पत्रकार से रचाई दूसरी शादी

-फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में ओम पुरी ने अपनी पहली शादी को लेकर कहा था कि उनकी पत्नी उनसे उम्र में काफी छोटी थीं और अपने मन की बात खुलकर उनके सामने नहीं रख पाती थीं। ऐसे में दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ीं और रिश्ता टूट गया।

-बाद में ओप पुरी की जिंदगी में पत्रकार नंदिता पुरी की एंट्री हुई जिनसे उनकी मुलाकात साल 1993 में फिल्म सिटी ऑफ जॉय की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों ने कुछ साल बाद शादी कर ली थी लेकिन समय के साथ इस रिश्ते में भी मतभेद सामने आने लगे थे। दोनों के स्वभाव और सोच अलग थे, फिर भी बेटे ईशान की खातिर उन्होंने साथ रहना जारी रखा।

नंदिता पुरी की किताब में हुए कई खुलासे

-नंदिता पुरी की लिखी किताब को लेकर भी विवाद हुआ था जिसमें ओम पुरी अपने निजी जीवन के खुलासों से नाराज थे। हालांकि समय के साथ उनका गुस्सा कम हुआ और उन्होंने बेटे की खातिर अपने शादी के इस रिश्ते को सम्मान देने का फैसला किया था।

-आपको बता दें कि नंदिता पुरी ने अपनी किताब में ओम पुरी की पर्सनल लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे जिसे लेकर एक्टर गुस्सा हो गए थे। नंदिता की लिखी किताब में ओम पुरी की निजी जिंदगी से जुड़े कई विवादित और बेहद व्यक्तिगत खुलासे सामने आए थे जिनमें उनके शुरूआती जीवन के कुछ अनुभवों और निजी रिश्तों का जिक्र किया गया है। बताया जाता है कि इन बातों के सार्वजनिक होने से ओम पुरी कि छवि पर असर पड़ा और वह इससे असहज हो गए थे।

'ओम पुरी ने मेरी बहन की लाइफ बर्बाद कर दी'

-वहीं अन्नू कपूर ने कहा कि अगर उनकी बहन ने ओम पुरी की देखभाल न की होती तो शायद उनका निधन 10 साल पहले ही हो जाता। उन्होंने बताया कि जब ओम पुरी की तबीयत खराब हुई तो वह दोबारा उनकी बहन के पास लौट आए थे। हालांकि बीते कड़वे अनुभवों के बावजूद अन्नू कपूर ने कहा कि अब उनके मन में इस बात को लेकर कोई नाराजगी नहीं है।

-अन्नू कपूर ने कहा- आज ओम पुरी साहब हमारे बीच नहीं हैं, उनका बेटा है। मैं आज भी उनके बेटे और उनकी पूर्व पत्नी नंदिता पुरी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन अफसोस है कि मेरी बहन सीमा कपूर की जिंदगी बर्बाद हो गई और आज उसके पास कोई सहारा नहीं है।

अपने गेम में बुरी तरह फंसे नेतन्याहू? थिओडोर हर्जल की नीति से भटकना कैसे पड़ रहा महंगा?

(जीएनएस)।

इजरायल के बनने के साथ ही उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा ज्यादा जोर दिया गया। पहले साल से लेकर अब तक इजरायल न जाने कितने युद्ध का हिस्सा रह चुका है और लगभग हर युद्ध एक बड़ी कामयाबी के साथ जीता। कभी अपनी शर्तें मनवाईं, कभी दुश्मन की जड़ काटी और कभी दुश्मन देश की जमीन भी अपने कब्जें में ली। लेकिन ये पहली बार है जब इजरायल अपनी ही डॉक्टरीन का शिकार होता दिख रहा है।

वर्तमान में ईरान के साथ चल रहे युद्ध में न तो उसे कुछ हासिल होता दिख रहा है और न ही उसके हिस्से में कोई जमीय या कामयाबी दिख रही है। उल्टा, इजरायली अब असुरक्षा के बीच जी रहे हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू को दोष दे रहे हैं।

इजरायली नेताओं ने अक्सर थिओडोर हर्जल के उस विजन का जिक्र किया है, जो उन्होंने 1896 में अपनी किताब "द ज्यूइश स्टेट" में रखा था। हर्जल ने लिखा था कि "फिलिस्तीन हमारा ऐतिहासिक घर है," और यह जगह यहूदियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनेगी। उनका सपना था कि यहूदियों को एक ऐसा देश मिले, जहां वे बिना डर के रह सकें। उन्होंने ये भी कहा था कि यह राज्य सिर्फ यहूदियों की सुरक्षा के लिए नहीं होगा, बल्कि यह उनके कल्चर का भी प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने पवित्र स्थलों की रक्षा और सभी धर्मों के सम्मान की बात भी कही थी।

फिर भी क्यों बनी हुई है असुरक्षा?

आज, 70 साल बाद, इजराइल एक मजबूत देश बन चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था, सेना और संस्थाएं दुनिया में मजबूत मानी जाती हैं। इन उपलब्धियों के बावजूद, इजराइल आज भी असुरक्षा के माहौल में जी रहा है। बार-बार के युद्ध, हिंसा और खतरे उसकी हकीकत बन चुके हैं। खासकर 7 अक्टूबर को हमास के हमले ने यह दिखा दिया कि मजबूत सैन्य ताकत भी हर खतरे को नहीं रोक सकती।

गाजा और लेबनान युद्ध ने बढ़ाई चिंता

हर्जल का जो आदर्श था, वह हाल की घटनाओं और विचारधार में टकराव दिखता है। गाजा और लेबनान में लंबे समय से चल रहे सैन्य अभियानों में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हुई है। इससे इजराइल की छवि और उसके मूल विजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

धार्मिक स्थलों पर विवाद ने बढ़ाया तनाव

इस साल कुछ घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी पैदा की। यरुशलम में कैथोलिक कार्डिनल को पाम संडे मनाने से रोका गया, और लेबनान में एक धार्मिक मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई। इन घटनाओं ने हर्जल की उस बात को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें सभी धर्मों के सम्मान का जिक्र था।

यरुशलम: विवाद का केंद्र

हर्जल ने यरुशलम को एक ऐसा शहर माना था, जहां सभी धर्मों को सुरक्षा मिले। लेकिन आज यह शहर राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय पूर्वी यरुशलम को फिलिस्तीन का हिस्सा मानता है,

जबकि इजराइल उसे अपना बताता है।

युद्ध के बीच मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

इस बार इजराइल ने स्वतंत्रता दिवस ऐसे समय मनाया जब देश युद्ध की स्थिति में है। 7 अक्टूबर के हमले का असर अब भी लोगों पर दिख रहा है। जश्न के बीच सायरन और सैन्य गतिविधियां यह याद दिला रही हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। आरोप ये भी हैं कि 7 अक्टूबर से पहले इजराइल को हमास की प्लानिंग के इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। यूनिट 8200 के कमजोरियां सामने आईं। मई 2024 में घुसपैठियों ने एक सैन्य अड्डे में प्रवेश कर जानकारी जुटा ली। इसके अलावा हजारों गोपनीय दस्तावेज ऑनलाइन लीक हो गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। इजराइल ने जवाब में दुश्मनों पर हमले करवाए, लेकिन इससे स्थायी समाधान नहीं निकला। गाजा और लेबनान में लंबे अभियानों के बावजूद यह साफ नहीं है कि आगे क्या होगा।

गाजा में अनिश्चित भविष्य

गाजा में युद्ध के बाद भी यह तय नहीं है कि वहां शासन कौन करेगा। दोबारा बसाने और बनाने को लेकर एक अधिकारी ने चेतावनी भी दी थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। यह सिर्फ खुफिया नहीं, बल्कि सोच की भी विफलता थी।

हमले के बाद भी सुरक्षा में खामियां

हमले के बाद भी कई सुरक्षा भी कोई रणनीति नहीं है। लिहाजा हमास को खत्म करने का लक्ष्य भी अधूरा नजर आता है। इजराइल के हमलों के बावजूद हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सर्वे बताते हैं कि फिलिस्तीनियों का एक बड़ा हिस्सा अब भी हमास का समर्थन करता है। यानी समस्या सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है।

योम हाज़िकारोन: याद और बलिदान

स्वतंत्रता दिवस से पहले योम हाज़िकारोन मनाया जाता है, जिसमें सैनिकों और हमलों में मारे गए लोगों को याद किया जाता है। यह दिखाता है कि इजराइल की आजादी कितनी बड़ी कीमत पर मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, माउंट हर्जल कब्रिस्तान अपनी क्षमता के करीब पहुंच चुका है। 7 अक्टूबर के बाद 1200 से ज्यादा सैनिकों के शव दफनाए गए हैं। इससे युद्ध की कीमत साफ दिखाई देती है।

क्या सैन्य ताकत ही समाधान है?

इजराइल ने कई सैन्य सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन स्थायी शांति अब भी नहीं आई है। गाजा, लेबनान और पूरे क्षेत्र में राजनीतिक समाधान की कमी बनी हुई है। थिओडोर हर्जल का सपना एक सुरक्षित और स्थिर राज्य का था। इजराइल ने ताकत तो हासिल कर ली, लेकिन स्थायी सुरक्षा अब भी सवाल बनी हुई है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है-क्या मौजूदा रणनीति शांति लाएगी या और संघर्ष को जन्म देगी?

यूपी बोर्ड के टॉपर्स पर बरसेगा सीएम योगी का प्यार! मिलेंगे 1 लाख नकद, जिले के होनहारों को भी मिलेगा तोहफा

(जीएनएस)।

यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं रिजल्ट जारी हो गया है. यूपी बोर्ड टॉपर में इस साल भी बेटियों का जलवा रहा. 10वीं और 12वीं में लड़कियों ने परचम लहराया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टॉपरों को बधाई दी है. यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स को योगी सरकार की ओर से नकदी समेत कई इनाम मिलते हैं.

बेटियों ने किया कमाल

जानकारी के मुताबिक, इस बार हाईस्कूल में 90.42 फीसदी परीक्षार्थी सफल हुए हैं. वहीं, बारहवीं में 80.38 फीसदी परीक्षार्थी सफल हुए हैं. खास बात यह है कि इस बार बोर्ड के रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा देखने को मिला है. दसवीं और बारहवीं दोनों की परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है. दसवीं और बारहवीं परीक्षा के रिजल्ट में लड़कियां टॉपर हैं.

सीएम योगी ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी छात्र—छात्राओं को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. सीएम योगी ने टॉपर को बधाई तो दी है साथ ही उन्हें प्राइज भी देंगे.

यूपी बोर्ड टॉपर्स को क्या-क्या मिलता है इनाम?

राज्य स्तर के टॉपर्स को सरकार लगभग 1 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार देती है. साथ में लैपटॉप या टैबलेट भी दिया जाता है. इसके अलावा मेडल और सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा. वहीं, जिला स्तर के टॉपर्स को करीब 21,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है. साथ ही सर्टिफिकेट और मेडल भी मिलता है.

गोरखपुर में सीएम योगी सख्त, जमीन विवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

जनता दर्शन में 200 लोगों की सुनी समस्याएं, अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश.

नई दिल्लीः (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन से जुड़े विवादों का निस्तारण विशेष टीम बनाकर तेजी से किया जाए. उन्होंने कहा कि जमीन का मालिकाना हक वास्तविक स्वामी को ही मिलना चाहिए और अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए.

सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुन रहे थे. उन्होंने सभी फरियादियों को आश्वस्त किया कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी. भूमि विवाद के मामलों में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चिकित्सा से जुड़ी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर मदद सुनिश्चित की जाए.

उन्होंने पुलिस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए.

कृषि विकास को लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर, मंत्री शिवराज सिंह चौहान

बोले- हर राज्य में बनेगा कृषि विकास का रोड मैप

(जीएनएस)।

लखनऊ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ के सेंट्रम होटल में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तर जोन के सम्मेलन में केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ नौ राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल हुए।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि देश के कृषि के विकास के लिए अब राज्य वार रोड मैप तैयार कर कम किया जाएगा। चौहान ने कहा कि सभी राज्यों में अलग-अलग स्थितियां और जलवायु क्षेत्र हैं। ऐसे में पूरे देश का एक रोड मैप बनाकर सही विकास नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राज्य अपनी-अपनी कार्ययोजना बनाएं, केंद्र उनको पूरी तरह सहयोग रहेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में गेहूं और धान की कोई कमी नहीं है। चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर वन पर पहुंच गया है, जबकि गेहूं का उत्पादन भी अतिरिक्त है और इसको निर्यात करने की भी अनुमति दी गई है। दलहन-तिलहन में भी आत्मनिर्भरता होना जरूरी है। सरकार का खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने पर जोर है। उन्होंने कहा नकली पेस्टिसाइड और बीज, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार पेस्टिसाइड और सीड एक्ट लाने जा रही है। यह बिल संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

सेंटर आफ एक्सीलेंस के माध्यम से बेहतरीन कार्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किसान वर्ष में एक फसल लेते थे, परंतु अब एक वर्ष में तीन-तीन फसल की जा रही हैं। वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तब हमारे पास 69 कृषि विज्ञान केंद्र थे, वह लगभग बंदी के कगार पर थे। आज कृषि विज्ञान केंद्र सभी नौ कृषि जलवायु क्षेत्रों में सेंटर आफ एक्सीलेंस के माध्यम से बेहतरीन कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह बदलाव वैज्ञानिक तकनीकों, एग्रो-क्लाइमेटिक जोन आधारित रणनीति तथा केंद्र-राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। यूपी में ह्वलैब टू लैंडह्व की अवधारणा धरातल पर उतर चुकी है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न एग्रो-क्लाइमेटिक जोन होने के कारण नीतियां भी उसी अनुरूप तय की जानी चाहिए। यदि अलग-अलग जोन में इस प्रकार की गोष्ठियां आयोजित की जाएं तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि गत वर्ष ह्यविकसित कृषि अभियान' और ह्यखेती की बात, खेत में' कार्यक्रम के दौरान उन्हें कई जनपदों में जाने का अवसर मिला, जहां किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि शिक्षा से जुड़े प्रशिक्षुओं में अभूतपूर्व उत्साह व जिज्ञासा देखने को मिली।

यूपी में 75 प्रतिशत फार्मर आइडी, सीखें अन्य राज्य

कृषि मंत्रालय के अपर सचिव प्रमोद कुमार ने क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देकर कहा कि देश के 19 राज्यों में अब तक 9.4 करोड़ फार्मर आइडी बनी है। यूपी 75 प्रतिशत आइडी बनाकर एक उदाहरण पेश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में 56 प्रतिशत, हरियाणा में 11 प्रतिशत और उत्तराखंड विचार जानने का एक अहम माध्यम होगा।

संवादात्मक कार्यशैली की झलक

राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह कदम उनकी पारदर्शी और संवादात्मक कार्यशैली को दशार्ता है। वे लगातार आम जनता से संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं व सुझावों को प्राथमिकता देने पर जोर देते रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। मुख्यमंत्री का यह लाइव सत्र भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

राजस्थान-दिल्ली विधानसभा में बम लगा दिए, मुसलमानों को बाहर निकालें', नोएडा में 2 संदिग्ध अरेस्ट

(जीएनएस)।

पहलगाम आतंकी हमले की बरसी के महज दो दिन बाद देश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राजस्थान विधानसभा के ऑफिशियल ईमेल पर भयानक बम धमकी मिली, जिसमें दिल्ली विधानसभा में 4 साइनाइड गैस बम लगाए जाने का दावा किया गया। साथ ही नोएडा में उत्तर प्रदेश अळर ने क्रक से जुड़े दो युवा आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों घटनाएं एक साथ सामने आने से पूरे उत्तर भारत में सनसनी फैल गई है।

धमकी भरे ईमेल का पूरा कंटेंट - सांप्रदायिक एंगल भी

सब्जेक्टः राजस्थान विधानसभा में ठीक दोपहर 1 बजे आत्मघाती धमाका, सभी मुसलमानों को बाहर निकालें!

मेल का मुख्य हिस्साः

'माननीय अध्यक्ष महोदय,

आशा है कि नई पुलिस सुरक्षा आपके लिए आरामदायक होगी।

आज की योजना सीधी-सादी हैः दिल्ली विधानसभा में पहले ही 4 साइनाइड गैस बम लगा दिए गए हैं। चेन्नई से छळळए और पाकिस्तान की क्रक द्वारा प्रशिक्षित 2 स्वयंसेवकों को जयपुर लाया गया है। वे अपनी साड़ियों या कमीजों के नीचे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (जैकेट) पहने होंगे। जब वे विधानसभा में रखे गए उन 4 बमों के बिल्कुल करीब पहुंचेंगे, तो बमों में लगा GPS अपने आप सक्रिय हो जाएगा और धमाका हो जाएगा। उन्हें आकर बम सक्रिय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।'

धमकी में साफ-साफ सांप्रदायिक भाषा इस्तेमाल की गई - 'सभी मुसलमानों को बाहर निकालें'।

राजस्थान विधानसभा में क्या हुआ?

शुक्रवार सुबह करीब 9:15 बजे ईमेल मिलते ही उच्च स्तरीय अलर्ट जारी किया गया।

ATS (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड)

बम निरोधक दस्ता

डॉग स्क्वॉड

तीनों टीमों ने पूरे विधानसभा परिसर को खाली करा दिया। 3 घंटे तक गहन तलाशी ली गई। कोई बम, विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। परिसर को सुरक्षित घोषित कर सामान्य कामकाज शुरू कर दिया गया।

इसी बीच उत्तर प्रदेश अळर ने नोएडा से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। दोनों ISI के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े थे।

गिरफ्तार संदिग्धों की पहचानः

तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान (बागपत, उम्र करीब 20 साल)

समीर खान (दिल्ली, उम्र करीब 20 साल)

बरामद सामानः पिस्टल, कारतूस, चाकू और 2 मोबाइल फोन।

अळर के मुताबिक दोनों श्क्ह लोगों के घरों पर ग्रेनेड हमले की साजिश रच रहे थे। वे क्रक के इशारे पर भारत के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश में शामिल थे।

दोनों घटनाओं का कनेक्शन?

धमकी वाले ईमेल में भी क्रक और छळळए का जिक्र है, जबकि नोएडा में गिरफ्तार दोनों युवक भी क्रक से लिंक्ड बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रही हैं। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि ईमेल और गिरफ्तारी के बीच कोई सीधा संबंध तो नहीं है।

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

राजस्थान विधानसभा और दिल्ली विधानसभा दोनों जगह अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात।

ईमेल का क्ह ट्रैकिंग, सेंडर की पहचान और क्रक के संभावित लिंक की जांच तेज।

ऐसे होक्स ईमेल पहले भी आ चुके हैं, लेकिन सांप्रदायिक एंगल और क्रक का जिक्र होने से मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है।

दोनों जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है। राजस्थान विधानसभा सामान्य रूप से चल रही है। नोएडा के गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ जारी है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर धमकी को गंभीरता से ले रही हैं। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर लाइव होंगे सीएम मोहन यादव, प्रदेशवासियों से करेंगे अहम संवाद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रात 9 बजे एक लाइव सत्र में निवासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें वे विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी पहलों और भविष्य की राज्य योजनाओं पर जानकारी साझा करेंगे, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और जन भागीदारी को मजबूत करना है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 24 अप्रैल की रात 9 बजे सोशल मीडिया पर लाइव आकर प्रदेशवासियों से महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करेंगे। इस संबंध में जानकारी उन्होंने स्वयं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की है।

मुख्यमंत्री के इस लाइव कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह और जिज्ञासा

का माहौल है। माना जा रहा है कि इस दौरान वे प्रदेश के विकास, जनकल्याण और भविष्य की योजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट (एक्स) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह आज रात 9 बजे लाइव आकर एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात प्रदेशवासियों के साथ साझा करेंगे। यह संवाद केवल औपचारिक नहीं, बल्कि जनता से सीधे जुड़ने और उनके

लखनऊ अग्निकांड में सब कुछ जलकर हुआ राख, फरिश्ता बनकर यूं की कई परिवारों की मदद

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ के विकासनगर स्थित झुग्गी बस्ती में पिछले दिनों लगी भीषण आग ने न केवल आशियाने जलाए, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों को भी राख कर दिया था. जहां कल तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां केवल काला धुआं और मलबे का ढेर बचा था. आपदा की इस घड़ी में जब प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे, तब राजस्थान के जोधपुर से उम्मीद की एक किरण ह्यफरिश्ता' बनकर आई.

जोधपुर स्थित ह्यट्रू होप फाउंडेशन' और इसके सह-संस्थापक धवल दर्जी ने लखनऊ पहुंचकर राहत कार्यों की कमान संभाली. उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने न केवल पीड़ितों को छत दी, बल्कि मानवता की एक मिसाल भी पेश की है.

आमतौर पर ऐसी आपदाओं के

बाद प्रशासन या संस्थाओं द्वारा तिरपाल या प्लास्टिक की पन्नियां बांट दी जाती हैं, जो गर्मियों में किसी भट्टी से कम नहीं होतीं. लेकिन धवल दर्जी और उनकी टीम ने तत्काल प्रभाव से *100 हीट-रेसिस्टेंट (ताप-रोधी) और वॉटरप्रूफ शेल्टर स्थापित किए.

बस्ती की एक बुजुर्ग महिला, जिनका सब कुछ जल गया था, नम आंखों से कहती हैं, ह्यबेटा, आग ने तो हमें सड़क पर ला दिया था, लेकिन इन बच्चों (फाउंडेशन की टीम) ने हमें फिर से इज्जत की छत दे दी. भगवान इन्हें बहुत तरक्की दे.'

जोधपुर के रहने वाले धवल दर्जी को हाल ही में 'डिजास्टर मैनेजमेंट हीरो अवार्ड' से सम्मानित किया गया है. True hope foundation ने अपनी तकनीक और जज्बे से उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया है जो सब कुछ खो चुके थे.

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के लिए अभी थोड़ा इंतजार; नहीं मिली एनओसी, उद्घाटन इस डेट तक संभव

लखनऊ से कानपुर की दूरी तय करने में अभी लगते हैं 2.5 से 3 घंटे, नए एक्सप्रेसवे से 30-45 मिनट लगेंगे.

लखनऊः , राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (नेशनल एक्सप्रेसवे-6) अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है. कुछ तकनीकी कमियों के कारण इसकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) अभी नहीं मिल सका है. अधिकारियों ने बताया कि इन कमियों को 15 मई तक दूर कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसका उद्घाटन किया जा सकेगा. इसीलिए गंगा एक्सप्रेसवे के साथ इसका लोकार्पण नहीं हो पा रहा है.

ठल्अक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि अभी 15 मई तक लोकार्पण नहीं किया जाएगा. कुछ काम अभी बाकी हैं. यह 63 किलोमीटर लंबा छह लेन का एक्सप्रेसवे लखनऊ के अमौसी क्षेत्र से शुरू होकर कानपुर के आजाद मार्ग (अजाद चौक) तक जाएगा. वर्तमान में लखनऊ-कानपुर के बीच NH-27 पर 90-94 किलोमीटर का सफर तय करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन नए एक्सप्रेसवे पर यह दूरी मात्र 30 से 45 मिनट में पूरी हो सकेगी. अधिकतम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इस एक्सप्रेसवे पर अनुमति नहीं होगी, केवल चार पहिया और भारी वाहनों के लिए यह एक्सेस-कंट्रोल्ड रहेगा.

पृष्ठभूमि और निमार्णः लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की महत्वाकांक्षी परियोजना है. यह राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का हिस्सा है, जो दोनों शहरों के बीच आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देगा. एक्सप्रेसवे दो पैकेज में विभाजित है. पहला पैकेज

लखनऊ में स्कूटर इंडिया से बनी (बन्थरा) तक लगभग 17.5 किलोमीटर का का है. यह मुख्यत एलिवेटेड सेक्शन है. जिसमें 10 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर और कई ब्रिज शामिल हैं. दूसरा पैकेज उन्नाव जिले में बनी से शुक्लागंज तक 45 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड सेक्शन है.

परियोजना में बड़े ब्रिज-अंडरपासः परियोजना में कुल चार बड़े ब्रिज, एक रेलवे ओवरब्रिज, कई अंडरपास (पैदल यात्री, हल्के वाहन आदि के लिए) और एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाया गया है.इसमें 100 से अधिक कैमरे भी स्थापित किए गए हैं, जो ओवरस्पीडिंग पर स्वतः चालान जारी कर सकेंगे. यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को सैकड़ों करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया.

एक्सप्रेसवे का बजटः एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 4,700 करोड़ रुपये है. इसमें सिविल वर्क्स पर करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि शेष राशि भूमि अधिग्रहण पर गई. प्रति किलोमीटर लागत औसतन 60-75 करोड़ रुपये के आसपास है, जो इसे यूपी के अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में अपेक्षाकृत महंगा बनाती है.

एक्सप्रेसवे का रूट

शुरूआतः लखनऊ -अमौसी (लखनऊ एयरपोर्ट के पास), शहीद पथ से कनेक्ट

मार्गः अमौसी, बनी (बन्थरा), कान्था, अमरसास, उन्नाव क्षेत्र, शुक्लागंज.

कानपुरः आजाद मार्ग (NH-27 जंक्शन के पास), जहां से उद्योग पथ से कनेक्टिविटी मिलेगी.

कुल लंबाई 62.764 किलोमीटर है. यह ठल्-27 के समानांतर बनेगा लेकिन ट्रैफिक जाम, सिग्नल और भीड़भाड़ से मुक्त रहेगा.

टोल गेट और टोल रेटः एक्सप्रेसवे पर पांच टोल प्लाजा प्रस्तावित हैं.ठल्अकने टोल दरें अंतिम रूप दे दी हैं, जो पुराने NH-27 से काफी ज्यादा लगभग 186% ज्यादा हैं. टोल की मुख्य दरें इस प्रकार हैं...

(कार/जीप/SUV के लिए): एक तरफा यात्राः ₹275

24 घंटे के अंदर वापसीः ₹415

अन्य वाहनों के लिए

हल्के कमर्शियल वाहन (LCV): एक तरफा ₹445, वापसी ₹670

बस और ट्रकः एक तरफा ₹935, वापसी ₹1,405

भारी वाहन (HCM): एक तरफा ₹1,020, वापसी ₹1,530

नियमित यात्रियों के लिए वार्षिक पास का विकल्प भी है, जिसकी कीमत ₹3,075 है. इससे बार-बार यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी. टोल दरें फास्टैग के माध्यम से स्वतः कटेंगी.

यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच दैनिक आवागमन को आसान बनाएगा, ईंधन की बचत करेगा और औद्योगिक विकास को गति देगा. कानपुर के उद्योगों, लखनऊ के प्रशासनिक केंद्रों और शिक्षा संस्थानों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

19 साल बाद ज्येष्ठ मास में पड़ेंगे आठ बड़े मंगल, लखनऊ में भंडारों के लिए नए नियम लागू

19 साल बाद ज्येष्ठ मास में आठ बड़े मंगल।

अधिक मास के कारण ज्येष्ठ माह 59 दिन का होगा।

भंडारों को स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील।

लखनऊ। (जीएनएस)। इस बार ज्येष्ठ मास में चार नहीं आठ मंगल पड़ेंगे और जगह-जगह भंडारे का आयोजन होगा। पांच मई को पहला पहला मंगल शुरू होगा। आचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि

इस साल ज्येष्ठ का महीना दो मई से लेकर 29 जून तक रहेगा। अधिक मास के कारण ज्येष्ठ माह पूरे 59 दिन का होगा। 19 साल बाद यह संयोग बन रहा है। इससे पहले 2007 में ज्येष्ठ मास में आठ मंगल पड़े थे।

इसलिए होता है अधिक मास

आचार्य आनंद दुबे ने बताया कि अधिक मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का एक विशेष महीना होता है। यह तब जोड़ा जाता है जब चंद्र वर्ष (लगभग 354 दिन) और सौर वर्ष (लगभग 365 दिन) के बीच का अंतर बढ़ जाता है।

इस अंतर को संतुलित करने के लिए हर ढाई से तीन तीन साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अधिक मास को बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस बार ज्येष्ठ मास में दो महीने का होगा।

उधर, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने शुक्रवार को कहा कि इस वर्ष बड़े मंगल को और भी विशेष बनाने के लिए भंडारों को स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त बनाना आवश्यक है।

पालीथिन, प्लास्टिक ग्लास, चम्मच और प्लेटों का उपयोग पूरी तरह बंद किया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ धार्मिक परंपरा का मान भी बढ़े। मंगलमान अभियान के संयोजक प्रो. रामकुमार तिवारी ने शहरवासियों से अपील की कि वे स्वच्छता और श्रद्धा के साथ भंडारे आयोजित करें। दो मई को सम्मान के साथ अभियान की शुरूआत होगी।